International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

पाकिस्तान के आर्थिक संकट में चीन की ऋण–जाल कूटनीति का प्रभाव: एक मूल्यांकन

डॉ. सतीश चन्द्र पाण्डेय[1], विशाल पाण्डेय[2]

[1] (आचार्य), रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन विभाग, दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

[2](शोधार्थी), रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन विभाग, दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

सारांश :

बाहरी ऋणों पर निर्भरता ने न केवल पाकिस्तान पर कर्ज का बोझ बढ़ा दिया है, बल्कि भविष्य में इन ऋणों को चुकाने की देश की क्षमता को लेकर भी चिंताएं बढ़ गई हैं। चीनी ऋण जाल कूटनीति ने पाकिस्तान के आर्थिक संकट को और बढ़ा दिया है, क्योंकि इन ऋणों की शर्तें अक्सर चीन के पक्ष में होती हैं, जिससे पाकिस्तान को अपने पुनर्भुगतान दायित्वों को पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इस ऋण जाल कूटनीति के परिणाम आर्थिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं हैं, क्योंकि इसने राजनीतिक बहस भी छेड़ दी है और पाकिस्तान की संप्रभुता और चीन के साथ उसके संबंधों पर भी सवाल उठाए हैं। इस शोध–पत्र ने वर्तमान समय में पाकिस्तान के सामने आने वाले वित्तीय मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है और कैसे राष्ट्र–राज्य न केवल आर्थिक उथल–पुथल में है, बल्कि चीन के साथ एक जटिल रिश्ते में भी है। इस शोध–पत्र में यह सवाल उठाया गया है कि क्या पाकिस्तान चीनी ऋण जाल में है, जिसमें पाकिस्तान में ऋण की प्रकृति, ऋण और संप्रभुता के बीच संबंध और आधुनिक समय में ऋण साम्राज्यवाद से कैसे जुड़ा है, इसकी जांच की गई है। इस शोध–पत्र ने सुझाव दिया है कि पाकिस्तान कर्ज के जाल में फंस गया है और यह सुझाव देने के लिए सबूत प्रदान किया है कि यह जाल चीन को लाभ पहुंचाता है और पाकिस्तान को कमजोर करता है, राज्य की संप्रभुता को खतरे में डालता है और पाकिस्तान को चीन के लिए लाभकारी गठबंधन में फंसाता है। नई सहस्राब्दी के बाद से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कर्ज में डूब गई है। चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के विकास के साथ चीन पाकिस्तान के ऋण चक्र का एक अभिन्न अंग बन गया है। इस बड़े पैमाने की बुनियादी ढांचा परियोजना ने सड़कों, रेलवे और बिजली संयंत्रों के विकास के साथ पाकिस्तान के लिए वित्तीय वरदान प्रदान किया है।

मुख्य शब्द : आर्थिक संकट, ऋण–जाल कूटनीति, चीन–पाकिस्तान सम्बन्ध,

प्रस्तावना :

ऋण–वित्तपोषित विकास की अवधारणा को अंतर्निहित किये बेल्ट एंड रोड पहल का 2017 में अनुमानित बजट $5 ट्रिलियन डॉलर था। आमतौर पर ऋण कूटनीति एक ऐसी प्रथा है जिसके तहत शक्तिशाली देश मेजबान द्वारा ऋणदाता की इच्छाओं के अनुपालन को आगे बढ़ाने के लिए ऋण संबंधों का लाभ उठाना चाहते हैं। इसमें आर्थिक और राजनीतिक दोनों मामलों की एक बड़ी संख्या शामिल हो सकती है, और इसलिए यह माना जाता है कि यह ऋण प्राप्तकर्ता देश के लिए हमेशा एक भूल साबित होता है। हालाँकि, यह देखते हुए कि प्राप्तकर्ता एक विकासशील राष्ट्र है और चीन एक बड़ी शक्ति है जो यह दर्शाता है कि पाकिस्तान गंभीर नुकसान में है। पाकिस्तान को केंद्र में रखकर यह प्रदर्शित करता है कि कैसे ऋण जाल आर्थिक संरचनात्मक परिवर्तन का कारण बनता है और यह विकास को नकारात्मक तरीके से कैसे प्रभावित कर सकता है।

हाल की घटनाओं और उनके निहितार्थों की समीक्षा की जाये तो यह ज्ञात होता है कि पाकिस्तान में आर्थिक संकट के हालिया संकट में है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कई कारक देखे गए हैं जिन्होंने इस प्रकार की स्थितियों में सक्रीय योगदान दिया है। अधिकांश विश्लेषणों में आमतौर पर नेतृत्व, नीति और प्राकृतिक संसाधनों कोमुख्य तत्व के रूप में शामिल किया जाता है। हालाँकि, वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को देखते हुए, यह तर्क दिया जा सकता है कि ऋण जाल कूटनीति के कार्यान्वयन के माध्यम से चीन की बढ़ती भागीदारी ने पहले से ही कमजोर पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था को निचले स्तर में लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चीन की विदेश नीति और अन्य देशों में उनकी स्व–रुचि वाली विकास पहल का मुद्दा इस बात का उदाहरण है कि वैश्विक क्षेत्र में आर्थिक संरचनात्मक परिवर्तन की गतिशीलता को अपने हितों की पूर्ति हेतु ही निश्चित है।

चीन की ऋण जाल कूटनीति एवं पाकिस्तान में चीनी निवेश

2013 में दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) समझौते में पाकिस्तान में बुनियादी ढांचे और ऊर्जा परियोजनाओं के लिए लगभग 62 बिलियन डॉलर के निवेश का प्रस्ताव था। हालांकि इसे पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम माना गया था, कुछ अंतर्निहित विशेषताएं हैं जिनके कारण इसे पूरे देश के लिए एक हानिकारक उद्यम के रूप में साबित हुआ । सीपीईसी निवेश का एक बड़ा हिस्सा ऋण है, अधिमानतः उच्च दरों पर, इस बीच जो परियोजनाएं बनाई जा रही हैं वे काफी हद तक ऊर्जा आधारित हैं। उपरोक्त ऋण के सभी भुगतानों का भुगतान पाकिस्तानी सरकार को तत्काल आधार पर करना होगा। हालाँकि कुछ ऊर्जा परियोजनाओं को पूरा होने में कुछ साल लग सकते हैं, लेकिन ऋण की अदायगी परियोजना शुरू होने से पहले ही शुरू हो जाती है। यह पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा दबाव है। ऋण को संप्रभु और गैर–संप्रभु ऋण में विभाजित किया जा सकता है, जहां पाकिस्तान का अधिकांश ऋण पूर्व का है। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स में कहा गया है कि दिसंबर 2018 में पाकिस्तान सरकार का सकल घरेलू उत्पाद का ऋण 86-10% था। ऋण में वृद्धि के परिणामस्वरूप देश की नीतियों में बाधा आती है क्योंकि आमतौर पर चीनी ऋण के साथ आने वाली शर्तों में चीनी पसंदीदा श्रम का कार्यान्वयन और चीनी की सुरक्षा शामिल होती है। अर्थात् चीन को जैसा हित उचित लगे। कर्ज़ में इस वृद्धि के परिणामस्वरूप पाकिस्तान की चीन पर निर्भरता बढ़ रही है जो चीन द्वारा पाकिस्तान का अधिकाधिक शोषण मात्र है।[1]

पाकिस्तान में चीनी निवेश और परियोजनाओं में पाकिस्तान के राजनीतिक अभिजात वर्ग के अपने निजी निहित स्वार्थ हैं। यह नीति कि सीपीईसी के परिप्रेक्ष्य में पाकिस्तान में अप्रत्यक्ष करों में बढ़ोतरी, कीमतों में बढ़ोतरी और या सरकारी उधार लेने और नई मुद्रा की छपाई की आवश्यकता होगी। इस तरह की कार्रवाइयों से बजट घाटे को बनाए रखने के लिए खर्च में कमी, उचित कर संग्रह और कर सुधार को तुरंत लागू करने में विफलता का कारण बना है। इससे पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था में अस्थिरता आई है. इसके अलावा, कर सुधार को लागू करने में विफलता से विदेशी निवेश में गिरावट और पाकिस्तान की आर्थिक स्थिरता में विश्वास की कमी भी हो सकती है। चीन के आक्रामक ऋण देने के लक्ष्य और रणनीतिक उद्देश्य छिपे हुए हैं जो स्पष्ट रूप से चिह्नित हैं। चीनी आंतरिक आकलन चीनी ऋणों को सुरक्षित करने वाली परिसंपत्तियों के जोखिम को अप्रासंगिक मानते हैं, हालांकि परिसंपत्तियों के रणनीतिक मूल्य की चिंता किए बिना, राज्य देनदार की परिसंपत्तियों के माध्यम से ऋण सुरक्षित करना जारी रखता है। चीनी रणनीति 'खराब ऋण' को इक्विटी में बदलना, पाकिस्तान की राष्ट्रीय संपत्तियों का स्वामित्व और नियंत्रण लेना है – जो सबसे रणनीतिक है।[2] स्पष्ट है कि चीन का लक्ष्य बड़ी शक्ति के रूप में अन्य बड़ी शक्तियों की स्थिति को पछाड़कर प्रभाव और शक्ति बढ़ाना है, ऐसा करने के लिए चीन को पार क्षेत्रीय संसाधनों व सहयोगियों की आवश्यकता है और वर्तमान में चीन संपार्श्विक आधारित समझौतों के माध्यम से इसे सुनिश्चित कर रहा है।

चीनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बी.आर.आई.) एशिया प्रशांत, अफ्रीका और यूरोप में 65 देशों को जोड़कर आर्थिक श्रेष्ठता हासिल करने, राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने और रणनीतिक बढ़त हासिल करने के उद्देश्य से एक व्यापक बुनियादी ढांचा और शक्ति गठजोड़ है। "ऋण जाल कूटनीति" प्रभाव क्षेत्र को इस तरह से बढ़ाने के लिए एक आक्रामक दृष्टिकोण है कि ऋण प्राप्तकर्ता देश, जो आमतौर पर अविकसित है, चीनी ऋणों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में सक्षम नहीं हो सकता है और असफलता की संभावनाओं में फंस सकता है। इसके परिणामस्वरूप, चीन राजनीतिक या रणनीतिक लाभ के रूप में ऋण भुगतान वापस मांगता है।[3] ऋण जाल कूटनीति का एक अनिवार्य हिस्सा किसी देश द्वारा चुकाई जाने वाली क्षमता से अधिक धन उधार देना है। जानबूझकर ऐसी स्थितियाँ स्थापित करके जिनका सम्मान करना कठिन है, चीन का लक्ष्य उन देशों की रणनीतिक संपत्तियों पर नियंत्रण करना है जिनका उपयोग उन देशों के वित्तीय संकट में पड़ने पर पुनर्भुगतान के रूप में किया जाना है। सीपीईसी के माध्यम से चीन की ऋण जाल कूटनीति को जानबूझकर ऋण निर्भरता की अवधारणा और मोटे उधार के शास्त्रीय उदाहरणों के संदर्भ में समझाया जा सकता है। चीन ने हमेशा सीपीईसी के इर्द–गिर्द यह प्रचार किया है कि यह पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण आयाम है और प्राप्त ऋण अर्थव्यवस्था को वापस उछाल देने में मदद कर रहे हैं। हालाँकि, आँकड़े बताते हैं कि अर्जित ऋण पाकिस्तान की आर्थिक समृद्धि के लिए एक गंभीर खतरा है। पाकिस्तान के स्टेट बैंक के अनुसार, चीन ने 2013 से लगभग 5.9 बिलियन डॉलर मूल्य के वाणिज्यिक ऋण की आपूर्ति की है। यह पिछले 60 वर्षों में पाकिस्तान को प्राप्त सभी वाणिज्यिक ऋणों का 30% है। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के अंत तक पाकिस्तान का विदेशी ऋण और देनदारियां मौजूदा 93% से बढ़कर 115% हो जाएंगी।[4] इसका मतलब यह होगा कि पाकिस्तान को इन ऋणों पर ब्याज भुगतान और अदायगी के लिए बजट में अधिक धन आवंटित करना होगा। इससे करों में वृद्धि होगी और खर्चों में भारी कटौती होगी, जो जनता के लिए स्वस्थ नहीं होगा और निजी क्षेत्र पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

पाकिस्तान का आर्थिक संकट

पाकिस्तान का आर्थिक संकट मुख्य रूप से कम आर्थिक विकास के कारण हुआ है। वैश्वीकरण के युग का अधिकांश समय पाकिस्तान की मानव और भौतिक पूंजी को विकसित करने में व्यतीत हुआ है। हालाँकि, परिस्थितिजन्य सरकारी निर्णयों और ऋण के साथ फेरबदल के कारण, धन को बड़े पैमाने पर गैर–विकास कार्यों में लगा दिया गया। कर्ज़ ने लगातार किसी भी निजी निवेश पहल को बाधित कर दिया है, और सरकार बड़े पैमाने पर कर राजस्व प्राप्त करने में असमर्थ रही है जो कि उसके राजकोषीय घाटे को भरने के

लिए पर्याप्त है। कर राजस्व की कमी के कारण, मुद्रास्फीति बढ़ गई है, और पाकिस्तान अक्सर पैसे छापने, रुपये का अवमूल्यन करने और इस प्रक्रिया में और अधिक मुद्रास्फीति और आर्थिक अस्थिरता पैदा करने का सहारा लेता है।

पाकिस्तान के आर्थिक संकट के दो मुख्य घटक हैं। सबसे पहले, भुगतान संतुलन संकट के कारण, पाकिस्तान अपने आर्थिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक व्यवस्थायों और उपकरण खरीदने में काफी हद तक असमर्थ रहा है। भुगतान संतुलन का यह संकट आज भी जारी है क्योंकि पाकिस्तान ऋण पूंजी को आकर्षित करने में सक्षम है जो पूंजी के बजाय विशुद्ध रूप से उपभोग को बनाए रखती है जिसे एक विशिष्ट समय अवधि के दौरान भौतिक और मानव पूंजी की खरीद से परिभाषित किया जाता है। इसका सीधा संबंध विदेशी निवेश से है। ऋण जाल के मुद्दे के कारण, पाकिस्तान के पास अब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) को आकर्षित करने की सीमित क्षमता है क्योंकि स्वामित्व और राजनीतिक और आर्थिक जोखिम के डर से, वे ऋण के माध्यम से निवेश का विकल्प चुनते हैं।[5] हालाँकि, चीन ने पाकिस्तान में तेजी से निवेश किया है, पहला चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारे में निवेश के माध्यम से और दूसरा पाकिस्तान की अब तक की प्रमुख आर्थिक बाधा, ऊर्जा, को हल करने में सक्रिय भागीदारी के रूप में इस बात की ओर स्पष्ट इंगित करता है कि ऋणों में बढ़ते निवेश के कारण पाकिस्तान अब कर्ज के जाल में फंस गया है। पाकिस्तान सरकार अपनी परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए चीन से ऋण पर बहुत अधिक निर्भर रही है। पाकिस्तान में चीनी निवेश के बीच, चीन ने देश को चीनी राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों और अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजार में युआन–मूल्य वाले बांड जारी करने के माध्यम से भारी मात्रा में ऋण प्रदान किया है। विश्लेषकों का मानना है कि पाकिस्तान को दिए गए ऋण के मामले में चीन का योगदान पिछले दशक में काफी बढ़ गया है। चीन ने पाकिस्तान को 6.14 बिलियन डॉलर के 17 ऋण प्रदान किए हैं। इन ऋणों में काराकोरम राजमार्ग के लिए 385 मिलियन डॉलर और कामरा में पाकिस्तान एयरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स के लिए 3.2 बिलियन डॉलर शामिल हैं। [cinews.com.pk](http://cinews.com.pk/ISLAMABAD): चीन ने पाकिस्तान के लिए ऋण के सबसे बड़े स्रोत के रूप में एशियाई विकास बैंक (एडीबी) को पीछे छोड़ दिया है, जो पिछले दस वर्षों में दो ऋणदाताओं के बीच अब तक का सबसे बड़ा अंतर है।[6]

पाकिस्तान की आर्थिक स्तिथि पार प्रभाव

चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारा पाकिस्तान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें 60 बिलियन डॉलर से अधिक की कई मेगापरियोजनाएं शामिल हैं, जो अगले 15 वर्षों में राजमार्ग, रेलवे और स्थानीय परिवहन प्रणालियों, एक नेटवर्क सहित शामिल होंगी(पाइपलाइनों, कई ऊर्जा परियोजनाओं, विशेष आर्थिक क्षेत्रों और ग्वादर में एक विस्तारित बंदरगा) इसने चीन द्वारा क्षेत्रीय स्वामित्व अर्जित करने की आशंका हेतु एक प्रेरक का काम किया है। अगले 20 वर्षों में चीनी निवेश पर पुनर्भुगतान प्रति वर्ष 3.5 अरब डॉलर होने का अनुमान है। इससे मौजूदा वार्षिक ऋण पुनर्भुगतान में सकल घरेलू उत्पाद का 2% जुड़ने की संभावना है, साथ ही निर्यात के लिए बाहरी ऋण का अनुपात बढ़ेगा, जो कम आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकता है।[7] मदीहा अफ़ज़ल के एक अध्ययन से पता चलता है कि मुद्रा मूल्यह्रास के कारण डॉलर–मूल्य वाले ऋण में वृद्धि हुई है और ईंधन लागत और सेवाओं के साथ कुछ परियोजनाओं से अतिरिक्त वित्तीय बोझ उत्पन्न होगा जो पाकिस्तान को व्यापक पर्यावरणीय क्षति का कारण बनेगा। एक आर्थिक क्षेत्र के रूप में ग्वादर राजनीतिक रूप से जोखिम कम करने वाले डिफ़ॉल्ट के मामले में साइट पर आगे स्वामित्व लेने के मामले में श्रीलंका के हंबनटोटा बंदरगाह के 99 साल के पट्टे के पैमाने पर 'ऋण–इक्विटी स्वैप प्रावधान' पेश कर सकता है। इससे संविदात्मक समझौते में हस्तक्षेप करने की संभावना है, जिससे मध्यस्थता के प्रयासों में बाधा आएगी। सबसे खराब स्थिति में, जहां वह चीन से ऋण चुकाने में असमर्थ है, पाकिस्तान अभी भी निर्मित क्षेत्र में चीन को कुछ दे सकता है।[8] बेहतरीन उदाहरण एक बिजली संयंत्र है जिसे पाकिस्तान में चीन द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है।

चीन स्पष्ट रूप से कठिन सौदेबाजी करता है। रेको डिक खनन मामले में मध्यस्थता खोने के कारण पाकिस्तान को फरवरी से जुलाई 2013 से जून 2016 तक निपटान का अंतरिम भुगतान मिला, जब 2017 में निवेश विवादों के निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र ने पाकिस्तान पर 5.97 बिलियन डॉलर का भारी जुर्माना लगाने की घोषणा की, जो वित्तीय वर्ष 2017 के राजस्व के 23.8% के बराबर है।[9] कार्की के साथ आंशिक समझौते में आरपीपी सफेद हाथी मामले में 9 अरब डॉलर के मध्यस्थ फैसले से फ्रांस में पाकिस्तान की मुख्य वाणिज्यिक संपत्तियों की कुर्की पर भी खतरा मंडरा रहा है। घरेलू संसाधन के रूप में चीनी ऋण की मान्यता इस प्रकार पाकिस्तान के स्टैंडअलोन क्रेडिट प्रोफाइल को प्रभावित करती है क्योंकि यह भुगतान संतुलन कठिनाइयों को उत्पन्न करता है और बाहरी भेद्यता को बढ़ाता है जिससे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई.एम.एफ.) पर निर्भरता के अंतिम उपाय की ओर अग्रसर होता है।

राजनीतिक निहितार्थ

ऋण जाल कूटनीति के पीछे अत्यधिक रणनीतिक उद्देश्य के अनुरूप, राजनीतिक निहितार्थ विशेष तौर पर चिंता का कारण होते हैं। सामान्यतः यह माना जाता है कि लिया गया ऋण ऋण देने वाले देश की ओर से राजनीतिक लाभ के लिए आर्थिक शक्ति का उपयोग कर सकता है। यदि ऋण प्राप्तकर्ता देश ऋण की शर्तों को पूरा करने में असमर्थ है, तो ऋणदाता देश परियोजना में इक्विटी के लिए,

या कुछ मामलों में क्षेत्रीय रणनीतिक भूमि हेतु शर्तें रखता है। दरअसल, श्रीलंका में हंबनटोटा बंदरगाह का मामला अक्सर इस चरम सीमा के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया जाता है कि यह किस हद तक घटित हो सकता है। परियोजना पर अपना ऋण चुकाने में असमर्थ होने के कारण, श्रीलंका को बंदरगाह को 99 वर्षों के लिए चीन को पट्टे पर देने के लिए मजबूर होना पड़ा। जबकि चीन इस बात पर जोर देता है कि यह व्यवस्था श्रीलंका द्वारा बिना किसी बाहरी प्रभाव के की गई थी, इससे क्षेत्र में नव–उपनिवेशवाद और क्षेत्रीय संप्रभुता के नुकसान की चिंताएं पैदा हो गई हैं। संप्रभुता के इस नुकसान को व्यापक राजनीतिक पैमाने पर भी दर्शाया जा सकता है जब ऋणी देशों को रिश्ते की लंबी उम्र सुनिश्चित करने के तरीके के रूप में ऋण देने वाले देश के हितों के साथ अपनी विदेश नीति को फिर से संरेखित करने के लिए मजबूर किया जाता है। यह क्षेत्र के मामलों पर पश्चिमी दुनिया और अन्य बहुपक्षीय संस्थानों के प्रभाव में कमी के रूप में प्रकट होता है। इसका उदाहरण पाकिस्तान को देखा जा सकता है।[10] जिनके बीच पारंपरिक रूप से घनिष्ठ संबंध हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका से आर्थिक या सैन्य सहायता पर भारी निर्भरता है। दोनों देशों में, चीनी संबंधों को बढ़ाने के पक्ष में अमेरिकी संबंधों से खुद को दूर करने के हालिया और चल रहे प्रयास स्पष्ट रूप से चीन के साथ उनके ऋणों से संबंधित हैं।

संप्रभुता पर प्रभाव

जिस तरह से चीनी कंपनियों को कुछ रियायतें और कर छूट की पेशकश की गई है, उससे पता चलता है कि उन्हें राजनयिक प्रोटोकॉल के तहत राजनयिकों के समान लाभ और छूट मिलेगी। इसका तात्पर्य राज्य और निजी फर्म, इस मामले में, सीसीपी के स्वामित्व वाली कंपनी के बीच समानता से है। इससे पाकिस्तान ऐसी स्थिति में आ सकता है जहां वह चीनी फर्म और राज्य के बीच भेदभाव करने में असमर्थ है, और चीनी कंपनियां कुछ मामलों में राजनयिक छूट की मांग कर सकती हैं। यह संभावित रूप से अपनी सीमाओं के भीतर अपने स्वयं के कानूनों और विनियमों को लागू करने की पाकिस्तान की क्षमता को कमजोर कर सकता है। कई उदाहरणों में, कुछ परियोजनाएं जिन्हें शुरू में सार्वजनिक–निजी भागीदारी कहा गया था, उन्हें बाद में बिल्ड–ऑपरेट–ट्रांसफर (बीओटी) आधार और ऋण वित्तपोषण मॉडल में परिवर्तित करने की घोषणा की गई।[11] ऐसा अपने निवेश की भरपाई के लिए इतनी लंबी अवधि में निजी निवेश की बाधा के कारण था।

चीन की कर्ज जाल कूटनीति का पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर भारी असर पड़ा है। फिर भी, सबसे अधिक अनदेखा और उपेक्षित प्रभावों में से एक पाकिस्तान की संप्रभुता पर है। चीन के नेतृत्व वाली बेल्ट एंड रोड पहल का पाकिस्तान में परियोजनाओं में हिस्सेदारी आवंटित करने और सुरक्षित करने पर भारी वित्तीय प्रभाव पड़ा है। विशेष रूप से, चीन ने पाकिस्तान के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश किया है, जो एक ऋण जाल समझौता है। यदि पाकिस्तान कर्ज चुकाने में असमर्थ है, तो चीन उसके ऋण को इक्विटी में बदल सकता है और ऊर्जा क्षेत्र का स्वामित्व ले सकता है, जैसा कि श्रीलंका के हंबनटोटा बंदरगाह के मामले में हुआ था।

निष्कर्ष एवं सुझाव

बेल्ट एंड रोड पहल, जिसका चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारा एक हिस्सा है, की स्थापना बुनियादी ढांचे के नेटवर्क बनाने और आर्थिक विकास और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। पाकिस्तान और अन्य जगहों पर चीन की भागीदारी अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में अपने राजनीतिक और आर्थिक दबदबे का विस्तार करने के लिए चीन के प्रोत्साहन से प्रेरित है। फिर भी, वैश्विक प्रिंट और ऑनलाइन मीडिया के साक्ष्य बताते हैं कि इस चीनी आर्थिक विस्तार का उधार लेने वाले देशों के लिए बहुत गंभीर और हानिकारक परिणाम होंगे। सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट जैसे चीनी विदेशी निवेश के आलोचकों का दावा है कि जब श्रीलंका हंबनटोटा बंदरगाह परियोजना के कारण अपना 8 बिलियन डॉलर का कर्ज नहीं चुका सका, तो चीन ने ऋण–इक्विटी व्यापार स्वीकार कर लिया, जिसका मतलब था कि बंदरगाह और उसकी जमीनें 1.12 मिलियन डॉलर मूल्य का ऋण समाप्त होने तक चीनी कंपनी के स्वामित्व में स्थानांतरित कर दिया गया। हालाँकि चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लू कांग इन दावों से इनकार करते हैं और कहते हैं कि चीन ने कभी भी अन्य देशों पर दबाव नहीं डाला है और उसकी कंपनियाँ व्यावसायिक रूप से निवेश कर रही हैं, चीन की नीतियों और हस्तक्षेपों से तय होने वाली एक नई, कमजोर अर्थव्यवस्था की संभावना हर दिन बढ़ती जा रही है। ऋण का स्तर. चीन ने हुआ चुनयिंग के माध्यम से कहा है कि उसका उद्देश्य देशों को सर्वांगीण विकास प्राप्त करने के लिए लोगों की आजीविका में सुधार करने में मदद करना है जो लोगों के लिए आर्थिक कल्याण, सामाजिक सुरक्षा और बेहतर जीवन लाता है। हालाँकि, यदि पाकिस्तान में ऋण का स्तर बढ़ता जा रहा है, और वर्तमान आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता ऋण की परिपक्वता तक बनी रहती है, तो चीन की नीतियां उधार लेने वाले देशों की राजनीतिक और आर्थिक स्वायत्तता को किस हद तक प्रभावित करेंगी, यह एक चिंताजनक प्रश्न है। यह खासतौर पर तब है जब अमेरिकी विदेश सचिव रेक्स टिलरसन जैसे नेताओं की ओर से पहले ही आर्थिक अस्थिरता और नव–साम्राज्यवाद की चेतावनी दी जा चुकी है। चीन–पाकिस्तान संबंधों की अच्छी संभावनाएं बनाए रखने के लिए, चीनी निवेश की शर्तों और इरादों पर स्पष्ट पारदर्शिता होनी चाहिए। वर्तमान पाकिस्तानी प्रदर्शनकारियों और संबंधित नागरिकों की नज़र में, इसका मतलब यह है कि चीन को चेहरा बचाने और हमेशा की तरह व्यवसाय चलाने के बजाय, वर्तमान स्थिति को सुधारने और भविष्य की पीढ़ियों के लिए राहत प्रदान करने में सरकार की मदद करनी चाहिए। इसने पाकिस्तान के ऊर्जा संकट के कई मुद्दों को संबोधित किया है और

उम्मीद है कि इससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की वृद्धि में 2% से अधिक की वृद्धि होगी। हालाँकि, इन सभी पहलों को ऋण और निवेश के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है। 2002 में सकल घरेलू उत्पाद के 29% से बढ़कर 2019 में आश्चर्यजनक रूप से 87% तक, देश की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए पाकिस्तानी सरकार के प्रयासों के बावजूद पाकिस्तान की ऋण समस्या में सुधार नहीं हुआ है। आलोचकों का तर्क है कि चीन पर पाकिस्तान की बढ़ती आर्थिक निर्भरता ने उसकी निर्णय लेने की स्वायत्तता से समझौता किया है और उसके राष्ट्रीय हितों को कमजोर किया है।

जैसे–जैसे चीन की शक्ति बढ़ती जा रही है और वह खुद को अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में शामिल करता जा रहा है, उसे कमजोर राज्य की समस्या का सामना बढ़ती आवृत्ति के साथ करना पड़ेगा। कमजोर देशों के साथ अपने आर्थिक संबंधों को प्रबंधित करने में, चीन इस दुविधा को कैसे संबोधित करता है, यह इस बात की पुष्टि करेगा कि वह किस प्रकार की शक्ति बनना चाहता है। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, अभी कुछ समय लगेगा जब उसका नेतृत्व आर्थिक आचरण के उस पद्धति को तोड़ने पर गंभीरता से विचार करेगा जिसके कारण बाहरी ऋण जीडीपी के 50% के करीब पहुंच गया है। लेकिन इस अनुभव ने उन पर भविष्य के अवसरों पर इस तरह की निर्भरता को दोहराने से बचने की आवश्यकता को प्रभावित किया है। यदि ऋणदाताओं का दबाव बढ़ता है, तो उन्हें कमजोरों की सदियों पुरानी रणनीति पर ध्यान देना होगा । अब, पाकिस्तान के राजनीतिक और सैन्य नेता, ऊपर से नीचे तक, असमंजस्य में हैं कि चीनी समर्थन ने उन्हें आत्मघाती कदम के सबसे बुरे परिणामों हेतु ही केवल अग्रसर किया। अफगानिस्तान में छद्म युद्ध, और उसके साथ सम्बन्ध बहाली पार ऋण जाल कूट नीति का प्रभाव है। लेकिन जब रियायती वित्त पर नरमी बरतना संरचनात्मक समायोजन के चीनी संस्करण में बदल जाता है, तो अधिक आकर्षक नए साझेदार के पक्ष में ग्राहक के निंदनीय परित्याग को तो छोड़ ही दें, उन्हें एहसास होता है कि राष्ट्रीय क्षमता और अंतरराष्ट्रीय सौदेबाजी की शक्ति के बीच संबंध का मतलब आकार देने के बीच का अंतर है। बाहरी कर्ताओं के साथ जुड़ाव की शर्तें और उनके रणनीतिक डिजाइनों का उद्देश्य होना। उनका मानना है कि यह उनकी कमजोर स्थिति है, न कि पाकिस्तान के प्रति चीन की रणनीति में कोई गलती, जिसके कारण चीनी व्यवहार में यह अवांछित बदलाव आया है।

हालाँकि पाकिस्तान अभी भी चीन के रणनीतिक हितों को पूरा करता है, लेकिन चीन के साथ इस रिश्ते को ऋणदाता द्वारा उधारकर्ता पर प्रभाव प्राप्त करने के एक उत्कृष्ट मामले के रूप में देखा जा सकता है। एक मजबूत अर्थव्यवस्था का निर्माण में बाधा मात्र है जो सत्ता को राजनीति के माध्यम से लाना चाहती है। पाकिस्तान जैसे कमजोर राज्यों में उन शर्तों को निर्धारित करने की क्षमता का अभाव होता है ।

बीआरआई के प्रति भारतीय प्रतिक्रिया स्पष्ट व विश्लेषण पार आधारित रही है जो यह दर्शाती है की ये परियोजना सम्पूर्ण दक्षिण एशियाई क्षेत्र हेतु खतरा है, आंशिक रूप से अक्साई क्षेत्र और डोकलाम पठार में चीन द्वारा किये जा रहे अतिक्रमण व् अत्यधिक विवादित क्षेत्र से गुजरने वाले चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के चीनी की आलोचना हुई है और यहां तक कि दोनों देशों के बीच सैन्य गतिरोध के साथ तनाव भी बढ़ गया है। भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने संसद को संबोधित करते हुए कहा कि "कोई भी देश ऐसी परियोजना को स्वीकार नहीं कर सकता जो संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर उसकी मूल चिंताओं को नजरअंदाज करती हो"। इस प्रतिक्रिया से संकेत मिलता है कि कुछ देश चीन की बीआरआई परियोजनाओं को अपनी संप्रभुता के लिए खतरे के रूप में देख सकते हैं और इन परियोजनाओं की दुष्चक्र का सभी विकल्पों से सामना कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, कई देशों ने चीनी ऋणों की शर्तों में पारदर्शिता की कमी और इन ऋणों के परिणामस्वरूप प्राप्तकर्ता देश के लिए ऋण जाल में फंसने की संभावना पर चिंता व्यक्त की है। उनका तर्क है कि पारदर्शिता की कमी के कारण प्राप्तकर्ता देशों के लिए ऋण के नियमों और शर्तों को पूरी तरह से समझना मुश्किल हो जाता है, जिससे वे ऋण जाल में फंसने और अपनी आर्थिक स्थिरता से समझौता करने के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। 'ऋण जाल' में चीन तीसरी दुनिया को बड़े पैमाने पर ऋण प्रदान के माध्यम से कुचक्र में फंसाता है । ये ऋण, ऋण जाल में बदल सकते हैं जब उधारकर्ता देश ऐसी स्थिति में होता है जहां चीनी ऋण का भुगतान करने का एकमात्र तरीका परियोजना में इक्विटी या यहां तक कि कुछ संपत्तियों पर संप्रभुता छोड़ना है। यदि उधारकर्ता चूक करता है, तो उन पर अक्सर उसी कंपनी के साथ ऋण पुनर्वित्त करने का दबाव डाला जाता है, अनिवार्य रूप से मौजूदा ऋण का भुगतान करने के लिए अधिक धन उधार लेना पड़ता है। इससे उधार लेने वाले देश के लिए कई जटिल राजनीतिक और आर्थिक समस्याएं पैदा हो सकती हैं, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर उन्हें शुद्ध घाटा होता है।

इस सन्दर्भ हेतु कुछ सुझाव निम्नं प्रकार है –:

- घरेलू फर्मों को अनुबंध सुरक्षित करने का समान अवसर दिया जाए,
- समझौते के वित्तीय नियमों और शर्तें को स्पष्ट होना चाहिए ।
- संबंधित विषयों और क्षेत्रों में उस राष्ट्र की तकनीकी विशेषज्ञता के निर्माण की आवश्यकता व् परियोजना निष्पादन के प्रभावी पर्यवेक्षण की सुविधा मिल मिलनी चाहिए
- चीनी कंपनियों द्वारा श्रमिकों के उपयोग संबधी नियमों में उदारता लानी चाहिए

- समझौतों की समीक्षा और नियमित रूप से ऑडिट करने के लिए एक निरीक्षण समिति की स्थापना करनी चाहिए
- एक बहु–संस्थागत समिति होनी चाहिए, जिसमें प्रत्येक संबंधित संस्थान या हितधारक का प्रतिनिधित्व होना चाहिए,
- अंतरराष्ट्रीय वित्त और निवेश, पर्यावरण विनियमन और बिजली उत्पादन, दूरसंचार और अन्य के प्रासंगिक तकनीकी विषयों में विशेषज्ञता वाले स्वतंत्र पेशेवरों का एक सचिवालय होना चाहिए।

सन्दर्भः

1. ZDW Putra - ECOCITY WORLD SUMMIT 2021-22 HOSTING …, 2022 - researchgate.net. Biking and Walking with COVID-19: The Comparison of Active Outdoor Activities Before and During The Pandemic in Yogyakarta. researchgate.net
2. Sial, F., Jafri, J., & Khaliq, A. (2023). Pakistan, China and the Structures of Debt Distress: Resisting Bretton Woods. Development and Change. wiley.com
3. G Xin, N Kiran - Journal of Development and Social Sciences, 2023 - ojs.jdss.org.pk. Development Path of Bilateral Economic Relations between Pakistan and China: Current International Situation. jdss.org.pk
4. Xin, G. & Kiran, N. (2023). Development Path of Bilateral Economic Relations between Pakistan and China: Current International Situation. Journal of Development and Social Sciences. jdss.org.pk
5. Sultani, A. H., & Faisal, U. (2022). Determinants of Balance of Payments: A Comparative Review of Developing and Least Developed Countries. International Journal of Research and Analytical Reviews, 9(2), 18-36. academia.edu
6. Singhaal, R. (2022). China's International Investments Under Xi Jinping: Long Term Implications of the Belt and Road Initiative and Asian Infrastructure Investment Bank. Inquiries Journal. inquiriesjournal.com
7. AH Khan, WA Hussain, RA Jamsheed - 2023 ,… المجلة العربية للعلوم الإنسانية - arabjhs.com. Impact of Government Investment and Chinese Investment on Economic Growth of Pakistan.. arabjhs.com
8. Z Khan, G Changgang, M Afzaal, R Ahmad… - … Chinese Economy, 2020 - Taylor & Francis. Debunking criticism on the China-Pakistan economic corridor. academia.edu
9. N Zia, B Burton - 2023 - books.google.com. Corporate Governance Challenges in Pakistan: Perceptions and Potential Routes Forward
10. Danger, A. E. (2022). … Road: Chinas Debt Trap for Asian Developing Countries and Through That Chinas Expansion of Infrastructure in Asia?: A Case and Comparative Study on Sri Lanka …. diva-portal.org
11. Naseer, A. (2022). BLUE DIPLOMACY AS FOREIGN POLICY INTRUMENT: CHALLENGES AND PROSPECTS FOR PAKISTAN (2002-2020). NATIONAL UNIVERSITY OF MODERN LANGUAGES. academia.edu